फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट का नया व्यवहार
(The 'New Deal' of Franklin D. Roosevelt)

1929-30 की आर्थिक मंदी ने अमेरिका की स्थिति बेहद नाजुक बना दी थी। देश के 40% उद्योग समाप्त हो गये थे, 1400 से अधिक बैंक फेल हो गये थे, किसान विद्रोह पर उतर आये थे तथा (25%) 1 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हो गये थे। देश का निर्यात अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुँचा था। बैंकिंग एवं साख व्यवस्था पूर्णतः अव्यवस्थित हो चुकी थी। ऐसी की विकट परिस्थिति में 1932 ई० के चुनाव में विजयी होकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमरीका के राष्ट्रपति बने। पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपना प्रथम कर्त्तव्य समझा — 'इस मंदी के दौर से राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर करना'।

यह एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए नवीन विचारों को अपनाने की आवश्यकता थी, और राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक योजना बनाई जो इतिहास में 'New Deal' के नाम से जानी जाती है।

New Deal एक बहुमुखी योजना थी, जिसमें राष्ट्रीय उत्थान के सभी पहलू शामिल थे। वस्तुतः रूजवेल्ट का उद्देश्य अपने नवीन कार्यक्रम के माध्यम से अधिक विकास समृद्धि की स्थापना करना था।

'न्यू-डील' के अन्तर्गत जो नीतियाँ अपनाई गई, उसे हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं —

(i) औद्योगिक नीति,
(ii) कृषि सम्बन्धी नीति,
(iii) सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान की नीति,
(iv) मुद्रा एवं साख नीति तथा
(v) पुनरीक्षण नीति।

रूजवेल्ट की नवीन अर्थ नीति के कार्यक्रमों को अंग्रेजी में तीन — 'R' अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है — 'Relief', 'Recovery' और 'Reform' अर्थात उन्मुक्ति, प्रतिलाभ एवं सुधार।

(1. औद्योगिक नीति :— आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए 1933 ई० में एक अधिनियम बनाया गया — 'राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरूत्थान अधिनियम'। इस अधिनियम का उद्देश्य था —

(A) व्यापार एवं उत्पादन का नियमन,
(B) पारिश्रमिक में वृद्धि,
(C) काम के घण्टों में कमी,
(D) मूल्य में वृद्धि आदि।

इस अधिनियम के द्वारा यह आशा की गई की कि —

(A) जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तथा
(B) अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 'राष्ट्रीय पुनरूत्थान प्रशासन' की स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप, रोजगार एवं मजदूरी में 1933 ई० के अंत तक क्रमशः 37% एवं 25% की वृद्धि हुई।

1935 ई० में 'वैगनर एक्ट' के द्वारा 'राष्ट्रीय-परिषद' की स्थापना की गई, जिसके द्वारा श्रम सम्बन्धी कार्यों पर नियंत्रण रखा गया।

1938 ई० में 'फेयर लेबर स्टैन्डर्ड्स एक्ट' द्वारा (i) न्यूनतम मजदूरी की दर 40 सेन्ट प्रति घण्टा तय की गई (ii) एक सप्ताह में अधिकतम काम की सीमा 40 घण्टे

(iii) 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक के रूप में रखना अवैध घोषित किया गया। तथा

(iv) 18 वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों को खतरनाक कार्यों के लिए नियुक्ति अवैध घोषित की गई।

(2) कृषि सम्बन्धी नीति :- इसके अन्तर्गत तीन मुख्य उद्देश्य रखे गये —

(i) किसानों की क्रय शक्ति तथा आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाना (अर्थात् कृषि पदार्थों तथा निर्मित वस्तुओं के मूल्य में समता स्थापित करना था।)

(ii) ग्रामीण कर्ज में कमी तथा मूल्य वृद्धि के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करना, तथा

(iii) किसानों के खेतों की गिरवी रखने से किसानों पर जो दबाव था, उसे कम करना।

किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 1933 ई० में कृषि समायोजन कार्यक्रम लागू किया गया। जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य थे —

(i) कृषि के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल में कमी,

(ii) जिस भूमि पर स्थायी रूप से खेती न करने की व्यवस्था की गयी, उसके बदले में लाभ देने की व्यवस्था, तथा

(iii) विपणन समझौतों द्वारा वैज्ञानिक विपणन व्यवस्था स्थापित करना।

इस अधिनियम की सर्वप्रथम वर्ष में कपास, गेहूँ तथा तम्बाकू पर लागू किया गया बाद में 1934 ई० में अन्य वस्तुओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया।